जनरल मैनेजर (मार्केटिंग) हिंदुस्तान फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

सुबोध चंद्र दास और अन्य।

29 जनवरी, 1988

[ई. एस. वेंकटरमैया और के. एन. सिंह, न्यायाधिपतिगण]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 226 - उच्च न्यायालय की शक्ति- जन्मतिथि में बदलाव के लिए कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका का दायरा- उच्च न्यायालय ने माना कि सेवा रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद 3 साल के लिए कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति को एक विशेष मामले के रूप में निर्देशित किया - क्या उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित करना उचित है।

पहला प्रतिवादी, अपीलकर्ता-निगम का एक कर्मचारी, जिसे नियोक्ता, अपीलकर्ता-निगम द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज जन्म तिथि के अनुसार 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1.6.89 को अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होना था, उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें दावा किया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा करते हुए उनकी जन्मतिथि को 20 अक्टूबर, 1938 में बदल दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता-निगम द्वारा याचिका का विरोध किया गया।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने माना कि पहले प्रतिवादी के मामले को स्वीकार करना संभव नहीं था कि उसका जन्म वर्ष 1938 में हुआ था, और अपीलकर्ता-निगम के रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, प्रतिवादी, घरेलू या अन्य, की समस्याओं पर विचार करते हुए उन्होंने इस आशय का आदेश दिया कि पहले प्रतिवादी को उसकी सेवानिवृत्ति की नियत तारीख के बाद एक विशेष मामले के रूप में उस अवधि के लिए पुनः नियुक्त करके तीन साल की सेवा दी जा सकती है।

अपील स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पाया कि अपीलकर्ता-निगम के रजिस्टर में दर्ज पहले प्रतिवादी की जन्मतिथि में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, अपीलकर्ता-निगम को निर्देशित करने वाला आदेश देने में गंभीर त्रुटि हुई। एक विशेष मामले के रूप में, पहले प्रतिवादी को उसकी सेवानिवृत्ति की नियत तारीख 1.6.89 के बाद तीन और वर्षों की अवधि के लिए इस आधार पर फिर से नियुक्त करना कि उसकी अपनी घरेलू या अन्य समस्याएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा आदेश पारित करने का शायद ही कोई औचित्य था। 1864 बी-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1068/1987

पटना उच्च न्यायालय सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 2523 /1981 में के निर्णय और आदेश दिनांक 16.5.86 से।

ए.के. सिल और एस.के. सिन्हा, अपीलकर्ताओं के लिए,

डी.एन. गोवर्धन, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

आदेश

प्रथम प्रतिवादी-सुबोध चंद्रा सिंधरी में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत ऑपरेटर ग्रेड-III के रूप में कार्यरत हैं। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि 1.6.1931 थी और सामान्य स्थिति में उन्हें 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1.6.1989 को सेवा से सेवानिवृत्त होना था। हालाँकि, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें दावा किया गया कि उनकी जन्मतिथि को बदलकर 20 अक्टूबर, 1938 कर दिया जाना चाहिए। अपने मामले के समर्थन में उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिंधरी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र पर भरोसा किया। याचिका का हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विरोध किया था। पक्षों के वकील को सुनने के बाद, याचिका पर सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि पहले प्रतिवादी के मामले को स्वीकार करना संभव नहीं है कि उसका जन्म उसी वर्ष 1938 में हुआ था और उन्होंने

आगे पाया कि निगम के रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> "एस. शम्सुल हसन, न्यायाधिपति.: मामले की लंबी सुनवाई के बाद और कानूनी तथा तथ्यात्मक पक्ष-विपक्ष की जांच करने के बाद यह प्रतीत हुआ कि याचिकाकर्ता के जन्म का वर्ष 1931 होने पर न तो चुनौती दी जा सकती है और न ही इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। नतीजतन, श्री ओझा ने महसूस किया कि चूंकि याचिकाकर्ता की समस्या घरेलू या अन्य है - और उन्हें 1971 में वास्तव में यह समझाया गया था कि उनका जन्म वर्ष 1938 होगा, इसलिए उनके पक्ष में कुछ अनुकंपा बंदोबस्ती की जा सकती है। मैं ओझा जी से पूरी तरह से इससे सहमत हूं। इसलिए, मैं अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ इस आवेदन का निपटारा करता हूं, जिसे एक आदेश के रूप में माना जा सकता है, कि याचिकाकर्ता को एक और तीन साल की सेवा उनकी सेवानिवृत्ति की नियत तिथि के बाद विशेष मामले के रूप में दी जा सकती है। विशेष मामला, जो उन्हें उस अवधि के लिए पुनः नियुक्त करके किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसे

संस्थान के किसी अन्य कर्मचारी या किसी अन्य मामले में एक मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि अपीलकर्ता-निगम के रजिस्टर में दर्ज प्रथम प्रतिवादी की जन्मतिथि में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, अपीलकर्ता को निर्देश देने वाला आदेश देने में गंभीर त्रुटि हुई- निगम 'एक विशेष मामले के रूप में' पहले प्रतिवादी को उसकी 'सेवानिवृत्ति की नियत तिथि', जो 1.6.1989 है, के बाद तीन और वर्षों की अवधि के लिए फिर से नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा आदेश पारित करने का शायद ही कोई औचित्य था। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण पूरी तरह से अप्राप्य है। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निगम द्वारा दायर की गई अपील को अनुमति दी गई है। हम उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं और पहले प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हैं।तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। लागत के हिसाब से कोई आदेश नहीं।

एन.पी.वी. अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।